**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS--- हिन्दुस्तान ----------DATED---15-11-2022

**राहत** | अदालत ने 35 हजार रुपये प्रति बीघा मुआवजा बढ़ाने के निर्देश दिए, 1965 में महरौली इलाके में याचिकाकर्ता ने 52 बीघा जमीन खरीदी थी

# अधिग्रहित जमीन पर 46 साल बाद मुआवजा बढ़ाया

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली की एक जमीन को विकास योजना के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अधिग्रहित किया। इस जमीन पर डीडीए ने वर्ष 1986 में कब्जा ले लिया। इस जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दायर की गई। अदालत ने अब इस जमीन के एवज में प्रति बीघा 35 हजार दो सौ रुपये बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

साकेत स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि मुआवजा बढ़वाने के लिए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में अदालत ने मृतक याचिकाकर्ता के उत्तराधिकारियों को बढ़ी मुआवजा रकम देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यह जमीन दक्षिणी दिल्ली के उस हिस्से से अधिग्रहित की गई थी जहां आज दिल्ली का एक पॉश इलाका बना है। यहां की कीमत बहुत ज्यादा है। अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि जिस समय याचिकाकर्ता को उसकी जमीन का मुआवजा दिया गया। उस समय उसकी जमीन की कीमत बहुत कम आंकी गई। जबकि उसके साथ ही जुड़ी अन्य जमीनों को अधिक मुआवजा दिया गया।

लिहाजा तमाम तथ्यों को देखते हुए 46 साल पहले अधिग्रहित की गई जमीन पर प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

**कई तरह के ब्याज भी देने होंगे:** अदालत ने डीडीए को कहा है कि इस जमीन पर 30 फीसदी सालाना हर्जाना ब्याज के रूप में याचिकाकर्ता के उत्तराधिकारियों को दिए जाएं। इसके अतिरिक्त 12 फीसदी सालाना ब्याज उस समय की वास्तविक जमीन की कीमत के आधार पर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस जमीन की बढ़ती कीमत के साल-दर-साल के हिसाब से भी डीडीए को सालाना ब्याज का भुगतान करना होगा।

## डीडीए ने कहा 92% मुआवजा बढ़ चुका है

डीडीए का अदालत में कहना था कि इस इलाके में अधिग्रहित की गई जमीन पर अलग-अलग समय पर मुआवजा बढ़ता रहा है। अब तक इस जमीन पर करीबन 92 फीसदी का मुआवजा बढ़ चुका है। परन्तु अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की याचिका में दिए गए तथ्य न्यायसंगत हैं।

## सीवर मौत मामले में डीडीए उपाध्यक्ष तलब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल की शुरुआत में एक सीवर के अंदर दो लोगों की मौत पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की उदासीनता देखते हुए सोमवार को सुनवाई की अगली तारीख पर डीडीए के उपाध्यक्ष की उपस्थिति के आदेश दिए हैं। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौ सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षा गार्ड की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। हादसा उस वक्त हुआ जब एक सफाईकर्मी सीवर की सफाई करने उतरा और बेहोश हो गया। बचाव के लिए दौड़ा एक सुरक्षा गार्ड भी बेहोश हो गया और दोनों की मौत हो गई।

**दैनिक जागरण** नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2022

# आदेश के बावजूद पेश नहीं हुए डीडीए उपाध्यक्ष, कोर्ट नाराज

- सीवरेज में जहरीली गैस के कारण दो कर्मियों की हो गई थी मौत
- घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, आज पेश होने का दिया आदेश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सीवर के अंदर जहरीली गैस के कारण हुई दो लोगों की मौत के मामले में आदेश का अनुपालन न करने व व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष को लेकर नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि अदालत ने पिछली सुनवाई पर डीडीए को पीड़ित परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा व 30 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति करने का आदेश दिया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में डीडीए उपाध्यक्ष को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होने को भी कहा था।

पीठ ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो अदालत के आदेश का अनुपालन हुआ और न ही उपाध्यक्ष पेश हुए। ऐसे में डीडीए उपाध्यक्ष को मंगलवार को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। सुनवाई के दौरान डीडीए की तरफ से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मुआवजा राशि दिल्ली सरकार को देनी है। इस पर आपत्ति उठाते हुए अदालत ने कहा कि डीडीए को निर्देश दिया था कि तत्काल पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि दी जाए। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि आपको पहले पीड़ित परिवार को भुगतान करना था और फिर उक्त धनराशि कानूनी प्रक्रिया के जरिये दिल्ली सरकार से लेनी थी। साथ ही पीठ ने डीडीए की अधिवक्ता से पूछा कि उपाध्यक्ष कहां हैं, आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना था। अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मुआवजा देने व अनुकंपा नियुक्ति पर कोई जवाब तक दाखिल नहीं किया। बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में नौ सितंबर को एक सफाईकर्मी और एक सुरक्षाकर्मी की सीवर में जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। सफाईकर्मी सीवर साफ करने के लिए नीचे गया तो बेहोश हो गया था। सुरक्षाकर्मी उसे बचाने गया तो वह भी बेहोश हो गया। दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था।

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**LIBRARY**
**PRESS CLIPPING SERVICE**

NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022

# Mix Of Old And New Promises To Make It A Tight Competition

## Delimitation, Reservation Force Parties To Change Wards Of Candidates

**Vibha.Sharma**
@timesgroup.com

Yogesh Verma, Bipin Bihari, Vikas Goel, Devender Chaudhary (L to R)

**New Delhi:** While a majority of candidates nominated by political parties are relatively new, there are some wards where experienced faces have been nominated again, which will make the competition tough.

The key wards where an intense battle is expected include Keshav Puram, Vinod Nagar, Dwarka B, Mayur Vihar-II, Daryaganj and Srinivaspuri.

BJP has nominated Yogesh Verma from Keshav Puram seat again. In the 2017-2022 tenure, he served as the Leader of the House, a member of the standing committee and a DDA member from the erstwhile north corporation. He will be facing AAP's Vikas Goel, who was Leader of the Opposition in the erstwhile north corporation during the same period and was continuously raising issues at every House meeting.

Goel was elected as councillor from Wazirpur, but after reservation of his ward due to delimitation, AAP decided to field him from Keshav Puram.

Asked about his chance of winning, Verma said, "After delimitation, 25 booths of my old ward (Keshav Puram) remained as it is, while 14 went to Ashok Vihar-I. I have been staying in Ashok Vihar for 40 years and people know me very well. The remaining 20 booths are from the neighbouring clusters, which were never visited by members of opposition parties in the past."

In Dwarka B, a reserved ward for women, the fight is between BJP's Kamaljeet Sehrawat and AAP's Sudha Sinha.

Former mayor in the erstwhile south corporation, Sehrawat won the poll with the highest margin (9,866 votes) in 2017. She served as Leader of the House and was considered a prominent councillor. Her opponent, Sinha, is president of Federation of Cooperative Group Housing Societies, Dwarka and constantly highlighted issues with the authorities and political functionaries.

"Being a representative of a residents' body for years, I'm aware of the challenges people face in getting any work done and how politicians should work to satisfy them all. I'm sure people will show confidence in me and help me win the election," said Sinha.

Sehrawat, however, emphasised that the ward has two villages, five unauthorised colonies, in addition to 186 group housing societies. "Residents of each of these areas are pretty aware about efforts undertaken by me," she added.

In Mayur Vihar-II, BJP's Bipin Bihari will be facing AAP's Devender Chaudhary. While Bihari served as a former mayor and member of committees, Chaudhary moved to AAP from BJP in March 2022. He had served as a councillor for two terms. "I was earlier mayor from Patparganj, but it has been reserved for women," said Bihari.

In Vinod Nagar, BJP's Ravi Negi will face a challenge from AAP's Kuldeep Bhandari. In the 2020 assembly elections, Negi gave a tough fight to deputy chief minister Manish Sisodia and lost the election with a close gap of 3,207 votes. In 2017, Negi couldn't contest the municipal election from the same ward as his nomination papers were rejected.

Former Congress member Kuldeep Bhandari, who joined AAP this year, fought the election from the same ward in 2017. But he lost to AAP's Geeta Rawat. After the anti-corruption branch arrested Rawat on corruption charges, the party gave the ticket to Bhandari.

In Daryaganj ward, former mayor, Leader of Opposition and senior Congress functionary Farhad Suri has been nominated by Congress again against BJP's Lalit Bhambri. In 2017, Suri's niece, Yasmin Kidwai, contested the election after the seat was reserved for women and won by a narrow margin of 59 votes. Bhambri's wife, Meeta, stood second and got 7,500 votes.

In Sriniwaspuri ward, former BJP councillor and zonal chairman Rajpal Singh will face AAP's Indu Verma. Verma was a two-time councillor from Congress (2002-2007 and 2007-2012) and joined AAP in 2021. She also held various positions during her tenure, including as the zonal chairman.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
TUESDAY, 15 NOVEMBER, 2022 | NEW DELHI
NAME OF NEWSPAPER

# Death of two in sewer: DDA's apathy egregious, says HC; seeks DDA vice-chairman's presence

**OUR CORRESPONDENT**

**NEW DELHI:** Calling "egregious" the "apathy" of the Delhi Development Authority over the death of two people inside a sewer earlier this year, the Delhi High Court on Monday sought the presence of DDA vice-chairman before it on the next date of hearing.

A sweeper and a security guard had died on September 9 in Outer Delhi's Mundka area after they inhaled toxic gases inside a sewer.

The incident occurred when a sweeper had gone down to clean the sewer and fainted. A security guard who rushed to his rescue also fell unconscious, and both died.

A bench headed by Chief Justice Satish Chandra Sharma, which was hearing a public interest litigation (PIL) initiated by the court on its own based on a news report of the incident, noted, admittedly, the compensation of Rs 10 lakh, as directed by the court, has not been paid to the family of the deceased by the DDA.

The bench, also comprising Justice Subramonium Prasad, further observed the DDA has not filed any documents in the case and the "Vice-Chairman, DDA, is also not present today for reasons best known to him". It noted there was no application from the official seeking exemption from personal appearance.

"The apathy exhibited by DDA, in the instant matter, is egregious in the opinion of this court. In view of the above, the Vice-Chairman, DDA, is directed to be present in court tomorrow," the bench ordered.

The court also directed the DDA to file an affidavit, as directed by it last month, on the issue of granting compassionate appointment to a member of the families of the deceased.

On October 6, the court had directed the Delhi Development Authority (DDA), under whose jurisdiction the incident took place, to pay Rs 10 lakh each as compensation to the families of the deceased and consider granting compassionate appointment.

It had also sought the presence of the vice chairman of the authority in case the order was not complied with till the next date of hearing.

The court had then remarked it was unfortunate that even after 75 years of Independence, the poor were forced to work as manual scavengers.

On September 12, the high court had taken suo motu cognisance of the two deaths and directed that a PIL be registered.